एल. जे. लीच एंड कंपनी लिमिटेड

बनाम

बनाम

जार्डिन स्किनर एंड कंपनी

(भगवती, वेंकटरामा अय्यर, बी. पी. सिन्हा और एस. के. एज़ जे. जे.)

वाद में संशोधन-दावे के लिए वैकल्पिक आधार को जोड़ना-वाद में मौजूद आवश्यक आरोप-संशोधित क्लैम पर नए सिरे से मुकदमा दायर करना, जिसे वर्जित किया गया है-क्या संशोधन के तहत कार्रवाई की अनुमति दी जानी चाहिए-जब भी उचित हो।

अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थियों के खिलाफ इस आरोप पर अंतरण के लिए हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया कि प्रत्यर्थी अपीलकर्ताओं के एजेंट थे, अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थियों के साथ कुछ वस्तुओं के लिए आदेश दिए थे, और यह कि प्रत्यर्थियों ने वास्तव में माल का आयात किया था लेकिन उन्हें अपीलकर्ताओं को देने से इनकार कर दिया था। मुकदमे को इस निष्कर्ष पर खारिज कर दिया गया कि पक्ष विक्रेता और खरीदार के संबंध में खड़े हैं, न कि एजेंट और प्रिंसिपल ए. एन. डी. कि माल में स्वामित्व केवल अपीलकर्ताओं को तब दिया जा सकता है जब उत्तरदाताओं ने उन्हें अपीलकर्ताओं के अनुबंधों के लिए विनियोजित किया हो। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, अपीलकर्ताओं ने वैकल्पिक रूप से, माल की डिलीवरी न करने के लिए अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाने का दावा करके शिकायत में संशोधन के लिए आवेदन किया। अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाने के दावे को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी आरोप पहले से ही शिकायत में मौजूद थे और एकमात्र आरोप की कमी थी कि अपीलार्थी, वैकल्पिक रूप से, माल की डिलीवरी न करने से अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाने का दावा करने के

हकदार थे। लेकिन संशोधित दावे पर एक नए मुकदमे को आवेदन की तारीख को सीमित करके रोक दिया गया था।

अभिनिर्धारित किया कि यह एक उपयुक्त मामला था जिसमें संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। यह तथ्य कि संशोधित दावे पर एक नए मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था, इस विवेकाधिकार के प्रयोग में ध्यान में रखा जाने वाला एक कारक है कि क्या संशोधन का आदेश दिया जाना चाहिए या नहीं, और न्याय के हित में आवश्यक होने पर इसे आदेश देने की अदालत की शक्ति को प्रभावित नहीं करता है। इसके बाद चरण दास बनाम आमिर खान, एल. आर. 47 आई. ए. 225 और किसान दास बनाम रचप्पा, (1909) आई. एल. आर. 33 बॉम्बे 644 आए।

वित्ति में एक कार्रवाई बनाए रखने के लिए वादी को यह स्थापित करना होगा कि उनके पास विचाराधीन माल का अधिकार था और जब वे प्रतिवादियों से उन्हें वितरित करने का आह्वान करते थे तो वे उस पर कब्जा करने के हकदार थे। यदि पक्ष लेन-देन के संदर्भ में विक्रेताओं और खरीदारों के संबंध में खड़े हैं, तो वादी को यह दिखाना होगा कि माल में संपत्ति, जो शुरू में प्रतिवादियों के पास थी, माल बिक्री अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें दी गई थी। हालाँकि, यदि प्रतिवादियों ने वादी के एजेंटों के रूप में माल का आयात किया, तो निस्संदेह उनका अधिकार बाद वाले के पास होगा, और तब एकमात्र सवाल यह होगा कि क्या पहले वाले कब्जा बनाए रखने के हकदार थे, जैसा कि वे होते अगर उन्होंने प्रिंसिपल की ओर से कीमत का भुगतान किया होता, और उस राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 1953 की सिविल अपील सं. 219

उक्त उच्च न्यायालय के 17 दिसंबर, 1951 के निर्णय और डिक्री से उत्पन्न 1952 की अपील संख्या 20 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के 26 जून, 1952 के निर्णय और डिक्री से अपील, 1948 के सूट संख्या 1623 में अपने सामान्य मूल नागरिक क्षेत्राधिकार में।

अपीलार्थियों की ओर से भारत के सॉलिसिटर-जनरल सी. के. डाफ्टरी, एम. एन. घारेखान और एम. एस. के. शास्त्री।

एच. डी. बानाजी, डी. पी. मदन, एस. एन. एंडले, रामेश्वर नाथ और जे. बी. दादाचंजी, प्रत्यर्थी के लिए।

22 जनवरी 1957 को न्यायालय का निर्णय
वेंकटरामा अय्यर द्वारा दिया गया था, जो बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपीलार्थियों द्वारा अंतरण के लिए 4,71,670-15-0 हर्जाने के लिए दायर एक मुकदमे से उत्पन्न हुई थी । मूल पक्ष में बैठे न्यायाधीश शाह द्वारा मुकदमे का फैसला सुनाया गया था, लेकिन चागला सी. जे. और न्यायाधीश गजेंद्र गडकर की अपील पर उनके फैसले को उलट दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ, वादी ने संविधान के अनुच्छेद 133 (1) (ए) के तहत प्रमाण पत्र पर वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी।

मेसर्स. मैटलैंड क्रेग लुब्रिकेंट्स लिमिटेड एक अमेरिकी कंपनी है जो स्नेहक के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है। इसने कलकत्ता में अपने मुख्य कार्यालय और बॉम्बे में एक शाखा कार्यालय के साथ भारत में व्यापार किया। दूसरे वादी, एच. जे. लीच, 1933 से 1935 के दौरान उक्त कंपनी की बॉम्बे शाखा में कार्यरत थे। इसके बाद, कंपनी ने अपनी बॉम्बे शाखा को बंद कर दिया, और अंततः अपने कलकत्ता कार्यालय को भी बंद कर दिया, और उसके बाद इसका व्यवसाय पहले इविंग एंड कंपनी और फिर प्रतिवादियों द्वारा ले लिया गया। मैटलैंड क्रेग लुब्रिकेंट्स

लिमिटेड की सेवा छोड़ने के बाद, श्री लीच ने अपने खाते पर स्नेहक विक्रेता के रूप में व्यवसाय शुरू किया और प्रतिवादियों के माध्यम से उनका आयात कर रहे थे। 6 जून, 1941 को उन्होंने एक समझौता किया, एक्स ए, जिसके तहत श्री लीच को बॉम्बे प्रेसीडेंसी, मध्य प्रांत, राजपूताना और मध्य भारत और हैदराबाद के ऐसे हिस्सों की सीमाओं के भीतर मैटलैंड क्रेग लुब्रिकेंट्स लिमिटेड से बने स्नेहक बेचने का विशेष अधिकार दिया गया था, जो प्रतिवादियों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यह समझौता पांच साल की अवधि के लिए जारी रहना था "जब तक कि इसके तहत दिए गए तरीके से जल्द से जल्द निर्धारित न किया जाए।" समझौते का खंड 14 इस प्रकार हैः

"इसमें पहले जो कुछ भी निहित है, उसके बावजूद यह समझौता किसी भी समय समाप्त होने वाले अन्य तीन कैलेंडर महीनों को लिखित रूप में पूर्व सूचना देने पर दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त किया जा सकता है, लेकिन पक्षकारों के अधिकारों और देनदारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो इस तरह की समाप्ति से पहले अर्जित हुए होंगे।"

खंड 16 में प्रावधान किया गया है कि समझौता बिक्री एजेंट के लिए व्यक्तिगत था, और यह कि उसे पहले प्राप्त लिखित रूप में प्रतिवादियों की सहमति के बिना अपने अधिकार सौंपने या सौंपने का प्रयास नहीं करना था। यह सामान्य आधार है कि संबंधित अवधि के दौरान इस समझौते के आधार पर पक्षों के बीच सौदे जारी रहे।

18 मार्च, 1944 को, पहले वादी, जो एक संयुक्त स्टॉक कंपनी है, को भारतीय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत शामिल किया गया था, और 30 मार्च, 1944 को, दूसरे वादी ने अपना व्यवसाय इसे सौंपा। 13 जून, 1945 को प्रतिवादियों ने दूसरे वादी को लिखा कि वे 6 जून, 1941 के समझौते के तहत गठित एजेंसी को रद्द कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लिखित रूप में उनकी सहमति प्राप्त किए बिना पहले वादी को यह काम

सौंपा था। हालाँकि, उस तारीख से पहले, प्रतिवादियों ने अमेरिका से कुछ वस्तुओं के आयात का आदेश दिया था, जिनकी वादी को आवश्यकता थी, लेकिन ये सामान वास्तव में अनुबंध रद्द होने के बाद उन्हें प्राप्त हुए थे। वादियों ने उनसे उन सामानों को उन्हें देने का आह्वान किया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद, वादियों ने अंतरण के लिए हर्जाने के लिए वर्तमान मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि विचाराधीन सामान पी. एल. 1004 से 1007 में शामिल सरकारी कोटा के तहत उन्हें देय था, और यह कि जिन प्रतिवादियों ने उन्हें उनकी ओर से आदेश दिया था, उनके पास उनका कोई अधिकार नहीं था। वादी ने यह भी कहा कि उन वस्तुओं के आयात में प्रतिवादी उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। अभियुक्तों ने इस दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि वे वादी के एजेंट होने की जगह, यह दूसरा वादी था जो उनका एजेंट था, और माल में संपत्ति प्रतिवादियों के पास थी और अंतरण के लिए नुकसान की कार्रवाई बनाए रखने योग्य नहीं थी।

मुकदमे की सुनवाई न्यायाधीश शाह द्वारा की गई, जिन्होंने यह अभिनिर्धारित किया कि वादी प्रतिवादियों के एजेंटों को नहीं मानते हैं, कि विचाराधीन सामान पूर्व की ओर से बाद वाले द्वारा आयात किया गया था, और उन्हें देने से इनकार करने पर, प्रतिवादी अंतरण के दोषी थे। तदनुसार उन्होंने नुकसान का पता लगाने के लिए आयुक्त को मुकदमा भेजने का आदेश पारित किया। अपील पर, चागला सी. जे. और जे. गजेंद्रगडकर ने अभिनिर्धारित किया कि 6 जून, 1941 के समझौते की शर्तों पर, जिस पर मुकदमा आधारित था, आयातित माल का स्वामित्व प्रतिवादियों के पास निहित था, और यह वादी के पास तभी जाएगा जब प्रतिवादी उनके पक्ष में प्रेषण दस्तावेज़ का समर्थन करेंगे, और जैसा कि ऐसा नहीं किया गया था, अंतरण के आधार पर हर्जाने का दावा गलत था। तदनुसार उन्होंने अपील को स्वीकार कर लिया और मुकदमे को खारिज कर दिया।

अब, हमारे सामने अपीलार्थियों का तर्क है कि साबित तथ्यों के आधार पर, वे अंतरण के आधार पर हर्जाने के हकदार थे। कानून की स्थिति को लेकर कोई विवाद नहीं है। इससे पहले कि वादी किसी कार्रवाई को जारी रख सकें, उन्हें यह स्थापित करना होगा कि उनके पास विचाराधीन माल का अधिकार था और जब उन्होंने प्रतिवादियों से उन्हें वितरित करने का आह्वान किया तो वे उस पर कब्जा करने के हकदार थे। यदि पक्ष लेन-देन के संदर्भ में विक्रेताओं और खरीदारों के संबंध में खड़े हैं, तो वादी को यह दिखाना होगा कि माल में संपत्ति, जो शुरू में प्रतिवादियों के पास थी, उन्हें माल बिक्री अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पारित की गई थी। हालाँकि, यदि प्रतिवादियों ने वादी के एजेंटों के रूप में माल का आयात किया, तो निस्संदेह उनका अधिकार बाद वाले के पास होगा, और तब एकमात्र सवाल यह होगा कि क्या पहले वाले कब्जा बनाए रखने के हकदार थे, जैसा कि वे होते अगर उन्होंने मूलधन की ओर से माल की कीमत का भुगतान किया होता, और उस राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती। हालाँकि, यह सवाल इस मामले के तथ्यों पर नहीं उठेगा, क्योंकि प्रतिवादियों ने माल पर वादी के अधिकार से इनकार कर दिया था, और बाद वाले ने कीमत का भुगतान करने से इनकार नहीं किया था। इसलिए, निर्धारण के लिए जो मुख्य प्रश्न उत्पन्न होता है, वह उस संबंध के बारे में है जिसमें पक्ष मुकदमे के लेन-देन के संदर्भ में खड़े थे।

यह स्वीकार किया जाता है कि शुरू करने के लिए, यह समझौता है, Ex ए, जो पक्षों के अधिकारों को नियंत्रित करता है। इसलिए इसके तहत पक्षों के वास्तविक संबंध का पता लगाने के लिए इसकी शर्तों की जांच करना आवश्यक है। यह पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि इस समझौते के तहत श्री लीच को उसमें निर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों में प्रतिवादियों का बिक्री एजेंट बनाया गया था। पूर्व के तहत। ए, दूसरा वादी माल को एक निश्चित कीमत से नीचे नहीं बेचना था, और उन्हें मैटलैंड क्रेग लुब्रिकेंट्स लिमिटेड के निशान के साथ भी बेचा जाना था। कार्य की प्रक्रिया यह थी कि दूसरा वादी प्रतिवादियों को अपनी आवश्यकताओं के

बारे में सूचित करता था। इसके बाद वे सी. आई. एफ. अनुबंधों के तहत अमेरिका से अपने नाम पर उन वस्तुओं का आयात करते थे। उन्हें आयात करने के बाद, वे उन वस्तुओं के लिए अपनी कीमत तय करेंगे और एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 443 दूसरे वादी के पक्ष में प्रेषण दस्तावेजों का समर्थन करेगा, जो कीमत के 80 प्रतिशत के भुगतान पर बंदरगाह पर उन्हें साफ़ करने का हकदार होगा, शेष 20 प्रतिशत का भुगतान उसके द्वारा अपने खरीदारों को माल की डिलीवरी पर देय होगा। क्षेत्र के भीतर दूसरे वादी द्वारा अपने ग्राहकों को की जाने वाली बिक्री ऐसे मामले थे जो केवल उसके और उसके खरीदारों से संबंधित थे। अभियुक्तों का उनसे कोई लेना-देना नहीं था। सी. एल. के तहत। 6, दूसरे वादी को "अपने स्टॉक के मूल्य को हर समय आग के जोखिम के खिलाफ पूरी तरह से बीमित रखना थाः "खंड 13 इस प्रकार हैः

"यहाँ पक्षों के बीच संबंध केवल मूलधन और मूलधन का होगा और बिक्री एजेंट के पास फर्म के नाम पर किसी भी व्यवसाय का लेन-देन करने या किसी तीसरे पक्ष के साथ या उसके साथ किसी अनुबंध, समझौते या उपक्रम द्वारा फर्म को बाध्य करने के लिए फर्म द्वारा लिखित रूप में उसे प्रदान किए जाने के अलावा कोई अधिकार नहीं होगा।

इन शब्दों के विपरीत, सी. एल. 4, है। जिसमें यह प्रावधान है कि प्रतिवादी स्वयं भारतीय भंडार विभाग को दूसरे वादी को आवंटित क्षेत्र के भीतर स्नेहक की अपनी सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति करेंगे, जिसे माल को साफ करने और उन्हें अधिकारियों को वितरित करने में उनके एजेंट के रूप में कार्य करना था। और इसके लिए, दूसरे वादी को एक कमीशन दिया जाना था।

यह स्पष्ट है कि समग्र रूप से पढ़ा गया समझौता एक समग्र समझौता है जिसमें दो अलग-अलग मामले शामिल हैं। जहाँ तक सी. एल. 4 का संबंध है, दूसरा वादी केवल प्रतिवादियों का एक प्रतिनिधि था। जहाँ तक अन्य खंडों का संबंध है, सच्चा संबंध है, जैसा कि सी. एल. 13, में कहा गया है कि दूसरा वादी प्रतिवादियों से माल का खरीदार था, और न्यूनतम मूल्य जिससे उन्हें बेचा जा सकता था और मैटलैंड क्रेग लुब्रिकेंट्स लिमिटेड के नाम से माल की अंकन से संबंधित शर्तों का उद्देश्य केवल उनके व्यापारिक हितों की रक्षा करना था, लेकिन एक बार जब प्रतिवादियों द्वारा दूसरे वादी को प्रेषण दस्तावेजों का समर्थन किया गया, तो वह उन वस्तुओं का मालिक बन गया। बीमा खंड का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दूसरे वादी द्वारा देय शेष मूल्य के संदर्भ में प्रतिवादियों के हितों की रक्षा करना था। इस मामले में, हम प्रतिवादियों द्वारा सी. एल.4 के तहत सरकार को आपूर्ति के लिए भेजे गए किसी भी सामान से संबंधित नहीं हैं। लेकिन उन वस्तुओं के साथ जो वादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके द्वारा आयात किए गए थे। उन वस्तुओं के संदर्भ में पक्षों का संबंध, यदि यह इस समझौते द्वारा शासित है, तो निस्संदेह यह है कि कोई भी पक्ष दूसरे का प्रतिनिधि नहीं है, और प्रतिवादी विक्रेता हैं और वादी खरीदार हैं। यदि ऐसा है, तो माल का अधिकार वादी को केवल तभी दिया जाएगा जब प्रतिवादी उन्हें अनुबंध के लिए विनियोजित करेंगे, उदाहरण के लिए, प्रेषण दस्तावेजों का समर्थन करके, और जैसा कि ऐसा नहीं किया गया था, रूपांतरण के आधार पर नुकसान के दावे को गलत समझा जाएगा।

अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान सॉलिसिटर-जनरल ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि पूर्व के तहत यह स्थिति थी। उ. लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि समझौते द्वारा बनाए गए विक्रेता और खरीदार के संबंध में तब संशोधन हुआ जब सरकार ने लाइसेंस प्रणाली शुरू की। यह अगस्त सितंबर, 1941 में शुरू किया गया था, जब युद्ध चल रहा था, आयात को विनियमित करने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से। अपनाई गई प्रणाली यह थी कि प्रत्येक आयातक को पिछले वर्षों के दौरान अपने

आयात व्यवसाय की सीमा के बारे में एक विवरण देना आवश्यक था, और उस विवरण के आधार पर उसे एक सीमा तक आयात करने का लाइसेंस दिया गया था। 26 सितंबर, 1941 को, दूसरे वादी ने स्नेहक आयात करने के लिए लाइसेंस के लिए नियंत्रक के पास आवेदन किया जिसमें कहा गया था कि वह सात साल से वह व्यवसाय कर रहा था और अपने व्यवसाय की मात्रा के बारे में विवरण दे रहा था। नवंबर में किसी समय, सरकार द्वारा उन्हें लाइसेंस दिया गया था। प्रतिवादियों ने अपने व्यवसाय की मात्रा के आधार पर स्नेहक आयात करने के लिए लाइसेंस के लिए भी आवेदन किया और इसे प्राप्त किया। उस लाइसेंस में वह मात्रा शामिल नहीं थी जो उन्होंने दूसरे वादी को बेची थी, और इस प्रकार दोनों लाइसेंस पारस्परिक रूप से अनन्य थे। श्री लीच स्वयं अमेरिका से सीधे माल आयात करने के लिए लाइसेंस के तहत हकदार होते, लेकिन उन्होंने पहले की तरह प्रतिवादियों के माध्यम से उन्हें आयात करने का विकल्प चुना, क्योंकि समझौते की शर्तों के तहत, एक्स ए, उसे माल की निकासी करते समय कीमत का केवल 80 प्रतिशत भुगतान करना होगा। हालाँकि, लेन-देन के स्वरूप में यह बदलाव आया था कि जबकि लाइसेंस प्रणाली से पहले प्रतिवादी सी. आई. एफ. अनुबंधों के तहत अमेरिकी कंपनियों के खरीदार थे और फिर उन्होंने दूसरे वादी को उनके द्वारा निर्धारित मूल्य पर सामान बेचा, लाइसेंस प्रणाली के तहत उन्हें देय मूल्य केवल वही था जो उन्हें खुद अमेरिकी विक्रेताओं को लेनदेन पर कमीशन के माध्यम से अतिरिक्त भुगतान करना था।

अब, अपीलार्थियों का तर्क है कि चूंकि वे उन्हें दिए गए लाइसेंस के तहत माल का आयात करने के हकदार व्यक्ति थे, इसलिए उनकी मांग पर उन्हें आयात करने में प्रतिवादियों को उनके लिए कार्रवाई करने के लिए माना जाना चाहिए, और यह कि उनके बीच संबंध अब एक्स ए के तहत विक्रेता और खरीदार का नहीं था, बल्कि एजेंट और मूलधन का था। इस पर उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री बानाजी का जवाब दो गुना था। उन्होंने सबसे पहले तर्क दिया कि अपने नाम पर लाइसेंस के

लिए आवेदन करने और प्राप्त करने में, दूसरा वादी केवल प्रतिवादियों के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा था, और दूसरा यह कि वर्तमान विवाद वाद में नहीं उठाया गया था और इसलिए अपीलार्थियों के लिए खुला नहीं था। पहले विवाद पर उन्होंने हमें उस पत्राचार का उल्लेख किया जो संबंधित अवधि में पक्षों के बीच पारित हुआ था। 5 सितंबर, 1941 को, प्रतिवादियों ने दूसरे वादी को कुछ शिपमेंट का विवरण भेजने के लिए लिखा ताकि वे उन्हें लाइसेंस के लिए अपने आवेदन में शामिल कर सकें, और 11 सितंबर, 1941 को, उन्होंने आगे उन्हें लिखा कि उन वस्तुओं को लाइसेंस के लिए उनके आवेदन में शामिल नहीं किया जाना था। लेकिन दूसरा वादी स्पष्ट रूप से इसके लिए सहमत नहीं था, और वास्तव में 26 सितंबर, 1941 को लाइसेंस के लिए अपने आवेदन में उन्हीं शिपमेंट को शामिल किया। प्रतिवादियों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया, और 10 दिसंबर, 1941 को दूसरे वादी को अपने आयात लाइसेंस की संख्या और तारीख सूचित करने के लिए लिखा और उस लाइसेंस के आधार पर उसके लिए माल का आयात करना जारी रखा। उत्तरदाताओं के वकील ने 11 दिसंबर, 1941 के एक पत्र पर भरोसा किया, जिसमें प्रतिवादियों ने दूसरे वादी को तेल व्यापारियों के एक समूह में शामिल होने की सलाह दी, जिसका गठन बॉम्बे में किया जाना था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक ग्राहक के रूप में उन्हें सलाह के रूप में था। यह साक्ष्य इस तर्क का समर्थन करने के लिए बहुत अनिर्णायक और बहुत छोटा है कि दूसरे वादी ने प्रतिवादियों के एजेंट के रूप में लाइसेंस प्राप्त किया था। दूसरी ओर, यदि एक्स ए के तहत दूसरे वादी की सही स्थिति यह थी कि वह माल का खरीदार था, तो उसके द्वारा उन सामानों की बिक्री मालिक के रूप में थी और उन बिक्री के आधार पर उसे जारी किया गया लाइसेंस उसे अपने अधिकार में दिया गया होगा न कि प्रतिवादियों के एजेंट के रूप में। यह शाह जे. का निष्कर्ष था और अपील पर इसे वापस नहीं लिया गया है, और हम इससे सहमत हैं।

इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि पूरी शिकायत इस आधार पर तैयार की गई है कि पक्षों के अधिकार एक्स ए द्वारा शासित हैं, कि इसमें कोई दावा नहीं है कि उस समझौते को रद्द या संशोधित किया गया था, और लाइसेंस प्रणाली शुरू होने के बाद एक नया समझौता प्रतिस्थापित किया गया था, कि बॉक्स में श्री लीच का सबूत यह भी था कि एक्स ए पूरी अवधि में लागू था, और इसलिए अब अपीलकर्ताओं के लिए यह तर्क देने के लिए खुला नहीं था कि एक्स ए के तहत विक्रेता और खरीदार के संबंध को एक एजेंट और मूलधन में बदल दिया गया था। यह सच है कि शिकायत इस आधार पर आगे बढ़ती है कि एक्स ए लागू है, और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि इसे संशोधित किया गया था। लेकिन एक्स ए को पूरी तरह से नहीं छोड़ा गया था। यह अभी भी मूल्य के 80 प्रतिशत के भुगतान पर माल की डिलीवरी जैसे विभिन्न मामलों के संबंध में पक्षों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए लागू था। शिकायत लाइसेंस प्रणाली की शुरुआत का उल्लेख करती है, और प्रतिवादी स्पष्ट रूप से वादी के रूप में इसके तहत सही स्थिति के बारे में जानते थे, और आश्चर्य का कोई सवाल नहीं हो सकता है। इन परिस्थितियों में, यदि पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण लाइसेंस प्रणाली के आधार पर किया जाना था, तो हम केवल इस आधार पर अपीलार्थियों पर मुकदमा दायर करने में संकोच करते कि उस प्रणाली का प्रभाव शिकायत में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था।

लेकिन फिर, लाइसेंस प्रणाली मार्च-अप्रैल, 1942 में समाप्त हो गई, और इसे "पट्टे और ऋण" योजना के रूप में जाना जाता है। यह इस योजना के तहत था कि इस मुकदमे की विषय वस्तु बनने वाली वस्तुओं का आयात किया गया था, और इसलिए हमें यह जांचना होगा कि पूर्व के साथ ली गई उस योजना की घटनाओं के संबंध में पक्षों के क्या अधिकार हैं। ए, जिसे अपीलार्थियों द्वारा लागू होने के लिए स्वीकार किया जाता है। यह योजना भारत सरकार द्वारा कुछ आवश्यक वस्तुओं के आयात को सुविधाजनक बनाने और युद्ध के प्रभावी अभियोजन के लिए उनके संरक्षण के लिए एक युद्ध उपाय के रूप में

शुरू की गई थी। तेल और स्नेहक उन वस्तुओं में से थे जिन्हें इस योजना के तहत नियंत्रित किया गया था। इसके तहत सरकार ने निजी एजेंसियों, चाहे वे व्यक्ति हों, फर्म हों या कंपनी हों, के माध्यम से अमेरिका से तेल और स्नेहक के सीधे आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और आवश्यक मात्रा में आयात करने की जिम्मेदारी ली।

कलकत्ता में आयातकों और विक्रेताओं के एक संघ का गठन किया गया था जिसे केंद्रीय स्नेहक सलाहकार समिति (C.L.A.C.) कहा जाता था, और आयातकों को समिति को लिखना था कि उन्हें अपनी ओर से कितनी मात्रा में आयात करने की आवश्यकता है। यह समिति एक निजी निकाय थी, और आयातकों और सरकार के बीच संपर्क के रूप में कार्य करती थी। बॉम्बे में इसी तरह की एक समिति का गठन किया गया था जिसे बॉम्बे लुब्रिकेंट्स एडवाइजरी कमेटी (B.L.A.C) कहा जाता था। माल के आयात में अपनाई गई प्रक्रिया यह थीः आयातकों को अपनी आवश्यकताओं को समिति को बताना था जिसने इसे सरकार को भेजा था। फिर सरकारी अधिकारियों द्वारा दी गई सूचना पर, विक्रेताओं को माल के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत के कारण जमा करना होगा। अमेरिका में सरकार का एक खरीद एजेंट था और उन्हें आवश्यक सामान खरीदने और कई विक्रेताओं द्वारा उल्लिखित भारत में गंतव्यों तक उन्हें भेजने की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। प्रेषण दस्तावेजों को सरकार के नाम पर लिया जाएगा और बंदरगाह पर मंजूरी के लिए आयातक को अनुमोदित बिलों का भुगतान किया जाएगा। इस प्रणाली की विशेषताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह सरकार थी जो माल का आयातक थी और विक्रेता केवल सरकार द्वारा उन्हें अनुमोदित किए गए शिपिंग दस्तावेजों पर ही माल के हकदार बन गए।

अब, जहाँ तक वादियों का संबंध है, तथ्य यह है कि उन्होंने सरकार के पास कोई जमा नहीं किया और उनका नाम उन व्यापारियों की सूची में नहीं था जिनके लिए सरकार ने माल का आयात किया था। उनका केवल

प्रतिवादियों के साथ सीधा व्यवहार था और उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को उन्हें भेज दिया। प्रतिवादियों ने सरकार को अपने आवेदन में वादी की आवश्यकता के साथ-साथ स्वयं की आवश्यकता को शामिल किया और सभी वस्तुओं के लिए आवश्यक जमा किया। लेकिन यह सब उनके नाम पर ही होगा। यद्यपि पक्षकारों के बीच पत्राचार के संदर्भ से यह पता लगाना संभव होगा कि प्रतिवादी द्वारा सरकार के साथ वादी की आवश्यकताओं के संबंध में दिए गए आदेशों में से कौन सा आदेश है, जहां तक सरकार का संबंध है, वह केवल प्रतिवादियों को आयातक के रूप में जानती थी, और यह उनके नाम पर था कि वह प्रेषण दस्तावेजों का समर्थन करेगी, और यह केवल तभी था जब प्रतिवादी अपनी बारी में उन्हें उसी का समर्थन करेंगे कि वादी को माल का स्वामित्व मिलेगा, और श्री लीच के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि यह उन प्रेषणों के संबंध में नहीं किया गया था, जिनके साथ मुकदमा संबंधित है। यही वह अपने बयान में कहता है-

"सभी सामान भारत सरकार के आदेश पर भेजे गए थे। सरकार को प्रस्तुत प्रत्येक व्यापारी को उसकी आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति की जाने वाली खेपों के संबंध में अलग-अलग दस्तावेज तैयार किए गए थे। जिन व्यापारियों ने अपनी आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया, उन्होंने बिलों की राशि का भुगतान करके माल का भुगतान किया। सरकार ने मुझे कोई आवंटन नहीं किया। मैं सरकार से अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए प्रतिवादियों पर निर्भर था। मैंने डीलर की आवश्यकता के अनुसार कोई नकद जमा नहीं किया। जो राशि मैं चाहता था, उसके संबंध में मैंने सरकार के पास कोई जमा नहीं किया। मेरी आवश्यकताओं के संबंध में भी प्रतिवादियों द्वारा सरकार के पास पूरी जमा राशि जमा की गई थी। प्रतिवादियों ने उन वस्तुओं के लिए मेरे पक्ष में दस्तावेजों का समर्थन किया जो मेरे लिए थे...। स्वीकृत भागों को छोड़कर पी. एल. के शेष भाग के लिए दस्तावेज 1004 से 1007 तक मुझे नहीं सौंपे गए थे या मेरे पक्ष में समर्थन नहीं किया गया था, सिवाय इसके कि माल की डिलीवरी किस हद तक की गई थी।

प्रतिवादियों के लिए सर जॉन बर्डर का साक्ष्य था "प्रेषण दस्तावेज प्रतिवादियों के नाम पर प्राप्त किए गए थे।" इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि पी. एल. 1004 से 1007 में शामिल वस्तुओं के संदर्भ में, जो मुकदमे का विषय था, प्रेषण दस्तावेज वादी के नाम पर नहीं बनाए गए थे, और न ही जिन प्रतिवादियों के नाम पर उन्हें लिया गया था, उन्होंने उनका समर्थन किया था। ऐसा होने पर, जब तक वादी यह स्थापित नहीं करते कि प्रतिवादी अपने एजेंट के रूप में माल का आयात कर रहे थे, उनके पास उनका अधिकार नहीं होगा, और रूपांतरण के आधार पर नुकसान का दावा विफल होना चाहिए।

हमें यह उल्लेख करना चाहिए कि अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादियों द्वारा लिखे गए कुछ पत्रों पर भरोसा किया जो दर्शाते हैं कि उन्होंने वादी को माल के स्वामित्व के रूप में मान्यता दी है। इस प्रकार, 12 अगस्त, 1944 को, प्रतिवादियों ने वादी को लिखा, "हम पुष्टि करते हैं कि खेप आपके लिए है", और 24 मार्च, 1945 को, उन्होंने लिखा, "हम इसके साथ एक बयान संलग्न करते हैं जिसमें उन मात्राओं और श्रेणियों को दिखाया गया है जिन्हें आदेश पी. एल. 1006/10 के खिलाफ सरकार द्वारा आपके खाते में आदेश दिया गया है।" लेकिन ये बयान प्रतिवादियों की स्थिति के साथ काफी सुसंगत हैं क्योंकि विक्रेताओं ने वादी की मांग पर माल का आदेश दिया था, और उस शीर्षक का आयात नहीं करते हैं जो उन्हें दिया गया था, जो माल के अस्तित्व में आने और विनियोजित होने के बाद ही हो सकता था। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ और प्रतिवादियों के नाम पर दस्तावेज भेजना जारी रहा। इसलिए हम विद्वान न्यायाधीशों से सहमत हैं कि दलीलों और साक्ष्य के आधार पर अंतरण के आधार पर हर्जाने का दावा विफल होना चाहिए।
इससे इस अपील को खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन वादी ने इस न्यायालय में याचिका में संशोधन के लिए आवेदन किया है, वैकल्पिक रूप से, माल की डिलीवरी न करने के लिए अनुबंध के उल्लंघन के लिए

हर्जाने का दावा किया है। उत्तरदाता आवेदन का विरोध करते हैं। उनका तर्क है कि संशोधन कार्रवाई के एक नए कारण का परिचय देता है, कि कार्रवाई के उस कारण पर एक मुकदमे को अब सीमा द्वारा वर्जित किया जाएगा, कि वादी के पास अपनी शिकायत में संशोधन करने का पर्याप्त अवसर था, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे, और समय बीतने के कारण प्रतिवादी गंभीर रूप से पूर्वाग्रहग्रस्त होंगे यदि इस नए दावे को उठाने की अनुमति दी गई थी। आपत्तियों में काफी बल है। लेकिन उन्हें उचित महत्व देने के बाद, हमारी राय है कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। वादी 13 जून, 1945 के नोटिस द्वारा समझौते को गलत तरीके से समाप्त करने के लिए किसी भी नुकसान का दावा नहीं करते हैं। वे जो दावा करते हैं वह केवल उनके द्वारा दिए गए आदेशों के संबंध में माल की गैर-डिलीवरी के लिए हर्जाना है और उस सूचना द्वारा समझौते की समाप्ति से पहले प्रतिवादियों द्वारा स्वीकार किया गया है। समझौते का खंड 14 स्पष्ट रूप से वादी के लिए उस अधिकार को सुरक्षित रखता है। सूट पूर्व पर स्थापित किया जा रहा है। ए, सी. एल. पर आधारित एक दावा 14 उन्हें वाद के दायरे के लिए विदेशी नहीं कहा जा सकता है। अभियोग की अनुसूची ई में उन कई आदेशों का उल्लेख है जिनके संबंध में प्रतिवादियों ने सामान देने से इनकार करके चूक की थी, और दावा किए गए नुकसान का भी उसमें उल्लेख किया गया है। वादी अपने संशोधन द्वारा केवल उन खेपों के संबंध में हर्जाने का दावा करने की मांग करते हैं। शिकायत में प्रार्थना अपने आप में सामान्य है और केवल हर्जाने का दावा करती है। इस प्रकार, अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाने के दावे को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी आरोप पहले से ही वाद में हैं। जिस चीज की कमी है वह केवल यह आरोप है कि वादी, वैकल्पिक रूप से, माल की डिलीवरी नहीं करने में प्रतिवादियों द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाने का दावा करने के हकदार हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालतें, एक नियम के रूप में, संशोधनों की अनुमति देने से इनकार कर देंगी, यदि संशोधित दावे पर एक नया

मुकदमा आवेदन की तारीख पर सीमा द्वारा बाधित किया जाएगा। लेकिन यह एक ऐसा कारक है जिसे विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या संशोधन का आदेश दिया जाना चाहिए, और यह न्याय के हित में आवश्यक होने पर इसे आदेश देने की अदालत की शक्ति को प्रभावित नहीं करता है। चरण दास बनाम अमीर खान (1) में प्रिवी काउंसिल ने कहाः

"यह कि संशोधन करने की पूर्ण शक्ति थी, इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है, और हालांकि एक नियम के रूप में ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जहां प्रभाव प्रतिवादी से एक कानूनी अधिकार को छीनना है जो उसे समय बीतने पर प्राप्त हुआ है, फिर भी ऐसे मामले हैं जहां इस तरह के विचार मामले की विशेष परिस्थितियों से अधिक भारी हैं। किसान दास बनाम रचप्पा (1) के माध्यम से

वर्तमान मामले में, पहले से ही निर्धारित वाद की सामग्री के अलावा, यह तथ्य है कि प्रतिवादियों ने सी. एल. की शर्तों का सख्ती से पालन किए बिना अनुबंध को रद्द कर दिया। 14. जिस आधार पर उन्होंने अनुबंध को अस्वीकार किया वह यह था कि दूसरे वादी ने पहले वादी को अपने हित सौंपे थे; लेकिन रिकॉर्ड से पता चलता है कि कार्य के बाद प्रतिवादियों ने दोनों वादी के साथ व्यावसायिक लेनदेन किया था और इसलिए रद्द करने का आधार वादी को उनके द्वारा दिए गए आदेशों के लाभों से वंचित करने का एक मात्र साधन प्रतीत होता है। हमारी राय है कि मामले के न्याय के लिए आवश्यक है कि संशोधन प्रदान किया जाना चाहिए। तदनुसार वादी को निम्नलिखित रूप में वाद में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगीः

"12 (क) वैकल्पिक रूप से और अंतरण के आधार पर दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वादी का कहना है कि उपरोक्त तथ्यों के कारण, पक्षों के बीच एक अनुबंध था जिसके तहत प्रतिवादियों ने वादी (या उनमें से किसी एक) को सरकार द्वारा उनके (वादी) खाते में आदेशित माल की

आपूर्ति और वितरण करने का बीड़ा उठाया था और इसे पी. एल. कोटा में शामिल किया गया था। 1004-पी. एल. 1007. उक्त माल बॉम्बे पहुँचा, लेकिन प्रतिवादी विफल रहे और मांग के बावजूद उसे वितरित करने में लापरवाही की, और वास्तव में वितरित करने के अपने दायित्व को अस्वीकार कर दिया। वादियों का कहना है कि वे हमेशा इसके लिए भुगतान करने और इसकी डिलीवरी लेने के लिए तैयार थे।

प्रतिवादी हर भौतिक समय पर अच्छी तरह से जानते थे कि वादी ने इसे पुनर्विक्रय और बिक्री और आपूर्ति के अनुबंधों को पूरा करने के लिए खरीदा था। वादी विवरण के अनुसार हर्जाने का दावा करते हैं।

इस अपील को तदनुसार अनुमति दी जानी चाहिए, अपील के तहत डिक्री को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए, और मुकदमे को निचली अदालत में फिर से सुनवाई के लिए भेज दिया जाना चाहिए। प्रतिवादी संशोधित दावे पर अपना लिखित बयान दाखिल करेंगे और मुकदमे की सुनवाई की जाएगी और कानून के अनुसार निपटाया जाएगा।
लागत का सवाल बना रहता है। चूंकि वादी को अनुग्रह प्राप्त हो रहा है, इसलिए उन्हें मुकदमे और बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील दोनों में प्रतिवादियों की लागत का भुगतान करना होगा। जहाँ तक इस अपील के खर्चों का संबंध है, क्योंकि प्रतिवादी अपने इस तर्क पर अड़े रहे कि वादी केवल अपने एजेंटों के रूप में काम कर रहे थे, एक ऐसा तर्क जो, यदि बरकरार रखा जाता, तो संशोधित दावे का भी निर्णायक जवाब देता, हम पक्षों को इस न्यायालय में अपनी लागत वहन करने का निर्देश देते हैं।

अपील की अनुमति दी गई। मामला प्रतिपेषण पर लिया गया है।

कमला देवी

बनाम

बाचो लाल गुप्ता [एस. आर. डी. ए. एस. सी. जे., भगवती और एस. के. डी. ए. एस. जे.]

हिंदू कानून-विधवा-बेटी के विवाह द्वारा अचल संपत्ति का उपहार दहेज-विवाह के बाद निष्पादित और पंजीकृत विवाह-वैधता-यदि संपत्ति के प्रत्यावर्तक हस्तांतरण अधिनियम (1882 का IV), धारा 123-हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (1956 का XXX), धारा 14 पर बाध्यकारी है। अपनी बेटी की शादी की शर्तों के निपटारे के अवसर पर किए गए एक विवाह-पूर्व वादे को पूरा करते हुए, बनारस स्कूल ऑफ हिंदू लॉ द्वारा शासित एक हिंदू विधवा ने विभाजन डिक्री द्वारा अपने हिस्से के लिए आवंटित 4 घरों के संबंध में उपहार का एक पंजीकृत विलेख निष्पादित किया, जिसमें शादी के लगभग दो साल बाद अपनी बेटी को उसके विवाह दहेज के रूप में दिया गया था। विभाजन डिक्री ने उसे आय का अधिकार दिया, लेकिन संपत्ति के कोष के साथ भाग लेने का कोई अधिकार नहीं दिया। उसके सौतेले बेटे एक घोषणा के लिए एक मुकदमा लाए कि उपहार का विलेख उसके जीवनकाल से परे शून्य और निष्क्रिय था और वापसी करने वालों को बांध नहीं सकता था। निचली अदालत ने पाया कि उपहार में दी गई संपत्तियां संपत्ति का एक उचित हिस्सा हैं।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक सपना राजपुरोहित की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।